भोपाल (मध्य प्रदेश) में "पशु रोग उच्च सुरक्षा प्रयोगशाला" का स्थापित किया जाना

2426. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चौदह करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश के भोपाल में एक "पशु रोग उच्च सुरक्षा प्रयोगशाला" स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार को हलाई खेड़ा में 13489 एकड़ भूमि प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोगशाला का निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रयोगशाला के निर्माण का कार्य पहले ही अप्रैल, 1991 में शुरू कर दिया गया है ।

प्रतिरक्षण टीका कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालकों को अनुदान

2427. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, पशुओं में "मुंहखुरी" (दांत संबंधी) बीमारी की रोकथाम करने के लिए प्रतिरक्षण टीका कार्यक्रम के अधीन कमजोर वर्गों के पशु मालिकों को शतप्रतिशत अनुदान प्रदान करने का विचार रखती है; और

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश निर्धन पशुमालिकों के काफी पशु इन निवारक टीके का अधिक मूल्य होने के कारण मर जाते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

गुजरात में नकदी फसलों की पैदावार

2428. **श्री राजूभाई ए. परमार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के वर्ष के दौरान गुजरात में नकदी फसलों की पैदावार कितनी हुई थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नकदी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए गुजरात को कितनी सहायता प्रदान की गई थी; और

(ग) गुजरात में नकदी फसलों की खेती के अधीन और क्षेत्र लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1991-92 के दौरान गुजरात में महत्वपूर्ण नकदी फसलों अर्थात् तिलहनों का उत्पादन 18.11 लाख मीटरी टन, गन्ने का उत्पादन 96.20 लाख मीटरी टन, कपास का उत्पादन 11.19 लाख गांठे (प्रत्येक 170 किलोग्राम की) तथा तम्बाकू का उत्पादन 1.58 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है ।

(ख) गुजरात को 1991-92 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 658.75 लाख रुपये तथा गहन कपास विकास कार्यक्रम के लिए 18.66 लाख रुपये की सहायता दी गई थी ।

(ग) सरकारी सहायता का मुख्य अभिबल नकदी फसलों के अंतर्गत आने वाली भूमि की उत्पादकता में एवं